श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, कही भी देश के किसी जिलें में पैसे की कमी महसूस नहीं की गई है । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, देश भर में applications registered are 3,28,41,664, Job Cards issued-2,45,64,480 and employment demanded-82,66,447महोदय, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में, जो ग्रेजुएट है, जैसा कि नारायणसामी जी agitate कर रहे थे, जो physical labour नहीं कर सकते थे, उन्होनें भी अपना नाम लिखा दिया । इस कारण इसमें संख्या ज्यादा हो गई है। लेकिन जो असल में employment demanded है, उसके लिए पर्याप्त राशि हरेक जिले में है । राशि की कमी के चलते कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जो यह महसूस करे कि पैसे के चलते काम नहीं दिया जा रहा है । महोदय, इसलिए हमारी इस पर नजर है । यह ठीक है कि कई ग्रेजुएट, एमए पास लोगों ने बेकारी भत्ता लेने के लिए इसमें अपना नाम लिखा लिया, लेकिन जब इन्होनें यह जाना कि इसमें physical labour करनी पड़ेगी, तब उन्होनें employment demand नहीं किया । इसीलिए हम इस फिगर को देख रहे हैं और इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है ।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS
Employment in Private Sector Industries under NREGA

†*383. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that private sector industries have assured to provide employment under National Rural Employment Guarantee Act;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) National Rural Employment Guarantee Act is a Central legislation under which State Governments are required to formulate schemes and identify works for providing employment to the job card holder wage seekers. The funds are shared by the Central Government and the State Governments as per the provisions of the Act. Private sector industries are not involved in the process of providing employment under the Act.

†Original notice of the question was received in Hindi.